SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

झारखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा के संवर्धन में बालिका आवासीय विद्यालय की भूमिका : समस्या एवं समाधान

कुमकुम कुमारी, शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग,
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

कुमकुम कुमारी, शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग,
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 28/04/2022
Revised on : -----
Accepted on : 05/05/2022
Plagiarism : 02% on 28/04/2022

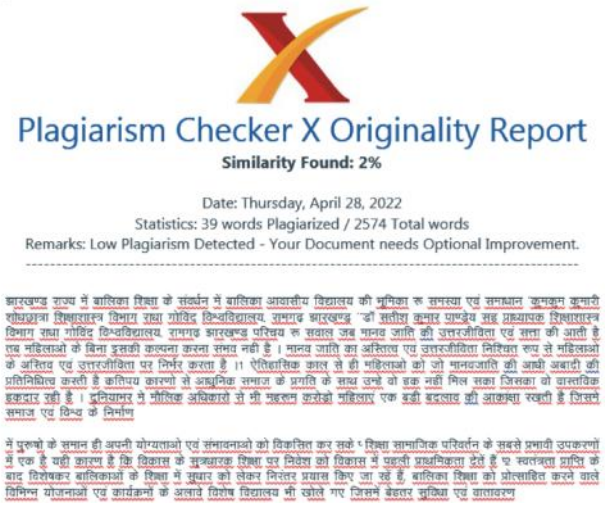

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 2%

Date: Thursday, April 28, 2022
Statistics: 39 words Plagiarized / 2574 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

झारखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा के संवर्धन में बालिका आवासीय विद्यालय की भूमिका रू समस्या एवं समाधान कुमकुम कुमारी शोधछात्रा शिक्षाशास्त्र विभाग राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ झारखण्ड `डॉ सतीश कुमार पाण्डेय सह प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र विभाग राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ झारखण्ड परिचय रू सवाल जब मानव जाति की उत्तरजीविता एवं सत्ता की आती है तब महिलाओं के बिना इसकी कल्पना करना संभव नही है । मानव जाति का अस्तित्व एवं उत्तरजीविता निश्चित रूप से महिलाओं के अस्तित्व एवं उत्तरजीविता पर निर्भर करता है ।। ऐतिहासिक काल से ही महिलाओं को जो मानवजाति की आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती है कतिपय कारणों से आधुनिक समाज के प्रगति के साथ उन्हें वो हक नहीं मिल सका जिसका वो वास्तविक हकदार रही है । दुनियाभर में मौलिक अधिकारों से भी महरूम करोड़ो महिलाए एक बड़ी बदलाव की आकांक्षा रखती है जिसमें समाज एवं विश्व के निर्माण

में पुरुषों के समान ही अपनी योग्यताओं एवं संभावनाओं को विकसित कर सकें ' शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रभावी उपकरणों में एक है यही कारण है कि विकास के मूल्यांकन शिक्षा पर निवेश को विकास में पहली प्राथमिकता देते हैं ए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा में सुधार को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावे विशेष विद्यालय भी खोले गए जिसमें बेहतर सुविधा एवं वातावरण

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र झारखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा के संवर्धन में आवासीय बालिका विद्यालय की समस्या और उसके समाधान विषय पर किया गया है। 2015–16 में किए गए झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं का नामांकन 50 प्रतिशत पायी गई है वहीं शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता 77.5 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता 56.2 प्रतिशत ही पाई गई, तो दूसरी तरफ पूरे देश की तुलना में स्कूल छोड़ने की दर भी झारखण्ड में दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आदिवासी छात्राओं में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक पाई गई है। इस समस्या के सार्थक समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए जिसमे 66 आवासीय बालिका विद्यालय और 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना उल्लेखनीय हैं। शोध अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इन विद्यालयों के संचालन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमे भौतिक अधोसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं का आभाव, स्थायी शिक्षकों का निरंतर आभाव, छात्रावासों के उचित प्रबंधन का अभाव, वित्त की ससमय आपूर्ति और आर्थिक प्रबंधन का आभाव, विभाग और विद्यालय में समन्वय का आभाव, निरंतर निरीक्षण का आभाव, स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय का अभाव, प्रथम चिकित्सा सुविधाओं का आभाव प्रमुख हैं, जिसके बिना बालिका शिक्षा के गुणात्मक लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। आवासीय विद्यालय की स्थापना से केवल संख्यात्मक लक्ष्य ही पूरे हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सामुदायिक सक्रिय जन भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए उत्तरदायित्व निर्धारण से ही उक्त समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है।

मुख्य शब्द

बालिका शिक्षा, आवासीय विद्यालय, गुणात्मक लक्ष्य, सामुदायिक सक्रिय जन भागीदारी.

परिचय

सवाल जब मानव जाति की उत्तरजीविता एवं सत्ता की आती है तब महिलाओ के बिना इसकी कल्पना करना संभव नही है। मानव जाति का अस्तित्व एवं उत्तरजीविता निश्चित रूप से महिलाओ के अस्तिव एवं उत्तरजीविता पर निर्भर करता है।[1] ऐतिहासिक काल से ही महिलाओ को जो मानवजाति की आधी अबादी की प्रतिनिधित्व करती है कतिपय कारणो से आधुनिक समाज के प्रगति के साथ उन्हे वो हक नहीं मिल सका जिसका वो वास्तविक हकदार रही है। दुनियाभर मे मौलिक अधिकारो से भी महरूम करोड़ो महिलाएं एक बडी बदलाव की आकांक्षा रखती है जिसमे समाज एवं विश्व के निर्माण में पुरूषो के समान ही अपनी योग्यताओ एवं संभावनाओ को विकसित कर सके। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रभावी उपकरणों में एक है, यही कारण है कि विकास के सुत्रधारक शिक्षा पर निवेश को विकास में पहली प्राथमिकता देतें हैं।[2] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा में सुधार को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा विशेष विद्यालय भी खोले गए जिसमें बेहतर सुविधा एवं वातावरण निर्माण कर बालिकाओं को गुणवतापूर्ण शिक्षा दिया जा सके। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्थापना इसका उदहारण है। विषम परिस्थितियों में जीवन–यापन करने वाली लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी यह महत्वकांक्षी योजना 2004 में प्रारंभ हुई और आज लगभग पुरे देश भर में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में केंद एवं राज्यों के सहयोग से संचालित हो रही है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य में राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हो रहें हैं।

ऐसा माना गया की नए राज्य के गठन से झारखण्ड यहाँ निवास करने वाले लोगो को विकसित होने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगें किन्तु राज्य गठन के 21 वर्षों के बाद भी आज विकास के मापदंडों में निचले पायेदान में अवस्थित राज्यों के साथ दिखलाई पड़ता है। यह इस राज्य की त्रासदी ही है कि अरबों रूपये की खनिज संपदा उत्पादन कर देश की राजस्व बढाने वाला यह राज्य अपने लाखों निवासीयों को तीनों समय का भोजन देने में सक्षम नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी इस वर्ष 2021 के सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में झारखंड बिहार और असम के साथ तीन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। भूख कम करने के मामले में राज्य सभी 28 राज्यों में सबसे नीचे रहा।[3] झारखण्ड शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति राष्ट्रीय औसत सूचकांकों से कम है, कहने का तात्पर्य यह है कि एक सक्षम राज्य के बावजूद झारखण्ड विकास के बुनियादी सूचकांकों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ, भोजन आदि के मामले पीछे है। वर्तमान आलेख झारखण्ड राज्य की मौजूदा परिस्थिति में बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु संचालित किए जा रहे बालिका आवासीय विद्यालय की वर्तमान स्थिति,समस्याएँ एवं इसके समाधान के संदर्भ में अनुभवात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति

किसी देश का वास्तविक स्थिति का अध्ययन वहां की महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक स्थिति से किया जाता हैं। महिलाओं की उनकी शैक्षिक स्थिति न सिर्फ उस समाज के इतिहास को समझने में सहायक है बल्कि भविष्य क्या होगा इसका भी निर्धारण संभव है।[4] 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार, झारखंड की जनसंख्या 3.3 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना में 2.69 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 32,988,134 है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 16,930,315 और 16,057,819 हैं। 2001 में, कुल जनसंख्या 26,945,829 थी, जिसमें पुरुष 13,885,037 थे जबकि महिलाएं 13,060,792 थीं।[5]

2015–16 में किए गए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन 50 प्रतिशत पाया गया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55.2 प्रतिशत की तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता 77.5 प्रतिशत थी। झारखंड में भारत में स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है (100 फिनिश स्कूल में से केवल 30)। आदिवासियों में स्कूल छोड़ने की दर सभी समुदायों में सबसे अधिक है। जबकि झारखंड ने संसद द्वारा पारित अधिनियम के मूल संस्करण से निकाले गए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों को निर्दिष्ट करके 2011 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम को अपनाया है।[6] झारखण्ड राज्य में 203 कस्तुरबा और 66 आवासीय विद्यालय समर्थ के नाम से संचालित हो रहे हैं, किंतु नामांकन, प्रतिधारण एवं विद्यालय छोड़ने संबंधी आकड़ें जो बताते हैं कि झारखण्ड में बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है।

झारखण्ड में साक्षरता की स्थिति

Literacy	66.41 %	53.56 %
Male Literacy	76.84 %	67.30 %
Female Literacy	55.42 %	38.87 %
Total Literate	18,328,069	11,777,201
Male Literate	10,882,519	7,646,857
Female Literate	7,445,550	4,130,344

(स्त्रोतः जनगणना 2011)[7]

बालिका आवासीय विद्यालय की वर्तमान स्थिति एवं बालिका शिक्षा के संवर्धन में इसकी भूमिका

झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहां पर अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और जीविकोपार्जन के दशाएं विषम है, बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना एक चुनौती वाला कार्य है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य स्तर पर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अत्यंत पिछड़े से पिछड़े ग्रामीण इलाकों के बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का समुचित अवसर प्राप्त हो। इसी आलोक में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए आरंभ किया गया। इसी तरह झारखंड सरकार भी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन लगभग हर जिले में कर रही है। राज्य में झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय की संख्या 66 हैं। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की संख्या 203 है। इन विद्यालयों की स्थापना से बालिका शिक्षा को गति एवं नई दिशा मिलने की आपार संभावनाएं है। कई समस्याओं के बावजूद आवासीय बालिका विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। हालाँकि राज्य में संचालित अन्य विद्यालयों की तरह ही स्थिति एक जैसी होने के कारण अभी इसे मील का पत्थर साबित होना बाकी है।

बालिका आवासीय विद्यालय की प्रमुख समस्याएं एवं समाधान

यूनेस्को के अनुसार गरीबी, भौगोलिक अलगाव, अल्पसंख्यक की स्थिति, विकलांगता, कम उम्र में शादी और गर्भावस्था, लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में पारंपरिक दृष्टिकोण, उन कई बाधाओं में से हैं जो महिलाओं और लड़कियों के अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने के रास्ते में आती हैं। जैसे कि शिक्षा में भाग लें, पूर्ण करें और लाभ उठाएं।[8] वास्तव ये समस्याएँ सामान्य रूप से शिक्षा अर्जित करने समेत सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं पाने के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी है, परंतु जहाँ तक झारखण्ड में बालिका शिक्षा के संवर्धन में बालिका आवासीय विद्यालय के समक्ष सम्स्याओं का प्रश्न है, यह निम्न हैं:

- **अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं का अभावः** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना का शुरुआत 2004 में हुआ, इसके साथ ही झारखंड राज्य में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की योजना शुरू की गई। इसके तहत अत्यंत ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के परिवारों के बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। किंतु लगभग

15 सालों के बाद भी कई क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवन एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के भवन बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। जबकि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कई जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्मित भवनों पर संचालित किए जा रहे हैं। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि आज भी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए जरूरी अवसंरचना, जैसेः भवन, पेयजल की सुविधाएं, शौचालय, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बालिकाओं के लिए हॉस्टल, खेल के मैदान आदि बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण जहाँ कई विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कि नामांकन की प्रक्रिया बाधित है, वही विद्यार्थियों का समुचित शिक्षा प्रदान करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- **स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का अभावः** यह अत्यंत चिंता की बात है कि जिस समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण विकास की पहली प्राथमिकता है उनकी शिक्षा के लिए स्थापित किए गए बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति आज तक लंबित है। अधिकांश कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय एवं झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षण का कार्य कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों के माध्यम से संपादित हो रहा है। अर्थात् महिलाओं की गुणात्मक रूप से शिक्षित करने की जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित शिक्षकों पर छोड़ दी गई है, जहाँ शिक्षकों को निम्नतम वेतन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षण अधिगम की अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने का उद्देश्य संभव नहीं है।
- **हॉस्टल का उचित प्रबंधन का अभावः** आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल का प्रबंधन अत्यंत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ रहने संबंधी व्यवस्थाओं को गंभीरता से ध्यान दिया जाता है, बल्कि भोजन, साफ सफाई, अनुशासन एवं स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है ताकि विद्यार्थी शिक्षण–अधिगम के साथ–साथ सामाजिक वातावरण एवं जरूरी सार्वभौमिक मूल्य का अर्जन कर अपने जीवन में जोड़ सके। किंतु पूरे झारखंड में संचालित हो रहे बालिका आवासीय विद्यालय के हॉस्टल की प्रबंधन व्यवस्था कई सवाल खड़ा करते हैं और समय–समय पर इसके खामियों एवं कमियों को न्यूज़ के माध्यम से हमें पढ़ने और सुनने को मिलते रहता है। अतः बालिका आवासीय विद्यालय में हॉस्टल का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चिंता है।
- **वित्त की कमीः** बालिका आवसीय विद्यालयों में सामान्य विद्यालयों की तुलना भारी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्त की कमी से न सिर्फ विद्यालय का संचालन प्रभावित होता है, बल्कि सभी तरह की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती है। झारखण्ड के अधिकांश आवासीय बालिका विद्यालय वित्तीय उदासीनता के कारण अपने प्रभाविता को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **आम जन की भागीदारी का अभावः** चुकि अधिकतर आवासीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं एवं यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के माता–पिता, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। शिक्षा के अभाव एवं आर्थिक असमर्थता के कारण इन आवासीय विद्यालयों के क्रियाकलापों में सक्रीय भागीदारी नहीं निभा पाते जबकि बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों का सक्रिय भागीदारी का सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वय का अभावः** हाल के वर्षों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में देखा जा सकता है, शिक्षा क्षेत्र इससे अछूता नहीं हैं। झारखंड राज्य में संचालित हो रहे बालिका आवासीय विद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं से स्थापना के समय से जुड़ा है। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि जहां यह विद्यालय के शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर इसकी प्रभाविता एवं उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही विद्यालय प्रबंधन में महती भूमिका निभाते हैं। किंतु स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय का अभाव चिंता का विषय है।
- **विभागीय निष्क्रियता एवं पर्यवेक्षण के कमीः** विभागीय निष्क्रियता एवं पर्यवेक्षण के कमी झारखंड राज्य में संचालित हो रहे बालिका आवासीय विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी छोटी समस्या जो विद्यालय के समक्ष है उसके समाधान में अनावश्यक देरी विभागीय निष्क्रियता को इंगित करता है। वही पर्यवेक्षण का

अभाव न सिर्फ निष्क्रियता को बढ़ाती है, बल्कि जटिलता को बढ़ाते जाती है। झारखंड राज्य में संचालित हो रहे बालिका आवासीय विद्यालय विभागीय निष्क्रियता एवं पर्यवेक्षण के कमी से जूझ रहें, इससे विद्यालय के संचालन में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त समस्याओं को ध्यान से देखा जाए तो हम पाते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किए बिना बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। झारखंड राज्य में बालिकाओं को विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कमजोर वर्ग के परिवारों के बालिकाओं को समुचित रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए संचालित किए जा रहे इन आवासीय विद्यालयों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए चाहिए कि इन विद्यालयों के सही तरीके से संचालन के लिए जरूरी अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं का समय रहते व्यवस्था किया जाय। जैसा कि अधिकांश बालिका आवासीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्ट आधारित शिक्षकों पर निर्भर हैं, ऐसे में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति गुणात्मक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य हो जाता है। इसी प्रकार क्योंकि आवासीय विद्यालयों में वित्तीय भार अन्य विद्यालयों की तुलना में काफी अधिक होता है इसलिए वित्त संबंधी बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक वित्त की व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाएं शिक्षण की उत्पादकता और विद्यालय प्रबंधन को सीधे रूप से प्रभावित करती है। चुंकि अभिभावक विद्यालय के गतिविधियों में सक्रिय सहयोग एवं रुचि नहीं रख पाते इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता उत्पन्न किया जाए एवं समाज कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि महिलाओं को शिक्षित किए बिना किसी देश के विकास को सुनिश्चित करना असंभव है इसलिए महिला शिक्षा वर्तमान समय में पूरी दुनिया में विकास के प्राथमिकताओं के क्रम में सबसे पहले स्थान पर है। भारत दुनिया का दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है जहाँ लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और पूरे दुनिया में युवा महिलाओं की संख्या देखा जाए तो भारत में ही है। इस दृष्टि से महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना भारत के लिए और भी जरुरी है। झारखंड जो कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा राज्य है में महिलाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम है। यही कारण है कि विगत वर्षों में सरकारों ने एवं स्वयंसेवी संगठनों ने महिलाओं की शिक्षा का संवर्धन करने के लिए कई एक प्रयास किए हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं झारखंड राज्य द्वारा प्रारंभ की गई झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की संकल्पना निश्चित रूप से बालिका शिक्षा में मील का पत्थर साबित होने की संभावनाओं को रखता है। किंतु जिस तरह से अवसंरचना का अभाव, वित्त की कमी, स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति का न होना, हॉस्टल के समुचित प्रबंधन का अभाव, स्वयंसेवी संगठनों के साथ आवासीय विद्यालयों का समन्वय का अभाव, प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी, विभागीय निष्क्रियता, पार्टी पॉलिटिक्स एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी की कमी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इसे दूर कर लिया जाए और आवासीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं व्यवस्था को ठीक करने में सरकार गंभीरता से कार्य करती है तो, निश्चित रूप से बालिका शिक्षा के संवर्धन में इन विद्यालयों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।

संदर्भ सूची

1. टूटी ऐतवा (2019). भारत में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की आवश्यकता एवं कुछ उभरते आयाम, रामचंद्र कुमार एवं माला मेश्राम (संपादित), २१ वीं शदी का भारत एवं डॉ भीम राव आम्बेडकर की प्रासंगिकता में, विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली, पृष्ठ संख्या 146–156।
2. वही पृष्ठ संख्या 146–156
3. मुकेश (04 जून, 2021)। झारखंड एसडीजी हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे, संपादकीय, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली इंग्लिश न्यूज पेपर, https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/jkhand-

at-bottom-of- sdg-hunger-index/articleshow/83215471.cms दिनांक 25.03.2022 को पुनः प्राप्त।

4. एक्का महेंद्र, (2019). महिला सशक्तिकरण एतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं आंबेडकर का योगदान, रामचंद्र कुमार एवं माला मेश्राम (संपादित), २१ वीं शदी का भारत एवं डॉ भीम राव आम्बेडकर की प्रासंगिकता में, विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली, पृष्ठ संख्या 54–64।

5. जनगणना (2011) census2011.co.in/census/state/jharkhand.html#:~:text=Literacy%20rate%20in%20Jharkhand%20has,literacy%20 is%20at%2055.42%20percent. दिनांक 25.03.2022 को पुनः प्राप्त।

6. सिंह, आयुषी, (3 अगस्त, 2020)। झारखंड में बालिका शिक्षा की स्थिति। SSRN पर उपलब्ध https://ssrn.com/abstract=3686884 या http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3686884. दिनांक 25.03.2022 को पुनः प्राप्त।

7. जनगणना (2011) census2011.co.in/census/state/jharkhand.html#:~:text=Literacy%20rate%20in%20Jharkhand%20has,literacy%20is%20at%2055.42%20percent. दिनांक 25.03.2022 को पुनः प्राप्त।

8. https://en.unesco.org/themes/education-and-gender-equality

9. कुमार, रामचन्द्र (2017) भारत में समावेशी शिक्षाः वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं समाधान, विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली, पृष्ठ संख्या 158–16।

10. कुमार, रामचंद्र (2017). इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ पावर्टी इनेकुँलिटी एंड एक्सक्लूशन विक्टोरियस पब्लिशर्स दिल्ली।

****